गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 212
दि. 03.12.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

मोबाइल सुरक्षा के नाम पर बढ़ता विवाद, 'संचार साथी' ऐप ने खड़ी कर दी निजता बनाम निगरानी की नई बहस-सरकार का यू-टर्न, विपक्ष का हमला और तकनीकी दुनिया की चिंता

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में मोबाइल फोन सुरक्षा को मजबूत करने के नाम पर शुरू किया गया 'संचार साथी' ऐप बीते तीन दिनों से राजनीति, तकनीकी जगत और आम जनता के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को एक आदेश जारी कर स्मार्टफोन निर्माताओं को निर्देश दिया था कि भारत में बिकने वाले हर नए फोन में यह सरकारी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए और इसे हटाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। यह आदेश जैसे ही सामने आया, देशभर में निजता को लेकर हड़कंप मच गया।

सोशल मीडिया से लेकर संसद तक, विपक्षी दलों से लेकर डिजिटल राइट्स संगठनों तक—हर तरफ इस ऐप को नागरिकों की निजी जिंदगी में राज्य की घुसपैठ बताया जाने लगा। स्थिति इतनी गरमाई कि मंगलवार को केंद्र सरकार को सफाई देकर तत्काल पीछे हटना पड़ा और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा—"संचार साथी ऐप अनिवार्य नहीं है। चाहे तो इसे डिलीट किया जा सकता है।"

लेकिन सरकार के इस यू-टर्न के बावजूद विवाद थमा नहीं है।

विपक्ष ने इसे डिजिटल जासूसी की साजिश बताया

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सबसे कड़ा बयान देते हुए कहा कि यह ऐप आम नागरिकों की निजी गतिविधियों पर नजर रखने का माध्यम है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह जानना चाहती है कि लोग किससे बात करते हैं, किससे जुड़े हैं, और उनके फोन पर

क्या चल रहा है।

शिवसेना (यूबीटी) की प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे निजता के अधिकार का सीधा उल्लंघन बताया और कहा कि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार सभी मोबाइल में जबरन अपना ऐप डलवाने की कोशिश कर रही है।

आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ कदम करार देते हुए कहा कि यह सरकार की बढ़ती "डिजिटल तानाशाही" का संकेत है।

तकनीकी जगत की प्रतिक्रिया—एपल का खुला विरोध

विवाद उस समय और गहरा गया जब अमेरिकी कंपनी एपल ने भारत सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया।

कंपनी का कहना है कि—

"संचार साथी ऐप सिम और यूजर डेटा की ट्रैकिंग से जुड़ा है, जो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। हम मौजूदा स्वरूप में इस आदेश को लागू नहीं कर सकते।"

एपल ने सरकार से बातचीत कर समाधान तलाशने की बात कही है, लेकिन उसका सीधा विरोध इस ऐप के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

सरकार का पक्ष—"जासूसी नहीं, सुरक्षा है मकसद"

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ऐप का मुख्य उद्देश्य चोरी हुए मोबाइल फोन खोजने, फर्जी IMEI नंबर पकड़ने और साइबर धोखाधड़ी रोकने में मदद करना है।

सरकार के अनुसार—

- 26 लाख फोन ऐप के जरिए ट्रेस हुए
- 7.23 लाख वापस लौटे
- 1.43 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए
- पोर्टल को 21.5 करोड़ से अधिक विजिट मिले

इन आंकड़ों को सरकार अपने बचाव के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन निजता को लेकर उठे सवाल इससे खत्म नहीं होते।

विवाद की जड़ क्या है

देश में पहली बार किसी सरकारी ऐप को अनिवार्य रूप से हर मोबाइल फोन में डालने की योजना बनाई गई थी।

आदेश में कहा गया था कि—

- ऐप को प्री-इंस्टॉल किया जाए
- इसे हटाया न जा सके
- पुराने फोनों में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसे जोड़ा जाए
- आदेश सार्वजनिक न करके कंपनियों को निजी तौर पर भेजा जाए

इन बिंदुओं ने विपक्ष और प्राइवेसी विशेषज्ञों को आशंकित कर दिया कि कहीं यह राज्य की व्यापक डिजिटल निगरानी का आधार तो नहीं?

निजता की लड़ाई लंबी—बहस फिलहाल खत्म नहीं

हालांकि सरकार ने फिलहाल इस योजना पर कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन डिजिटल प्राइवेसी और सरकारी निगरानी को लेकर उठी बहस एक बार फिर तेज हो गई है।

देश में डेटा संरक्षण को लेकर अभी भी कई प्रावधान विवादों में हैं और निगरानी व्यवस्था को लेकर स्पष्ट नीतियां नहीं बन पाई हैं।

संचार साथी ऐप पर मचा यह विवाद यह एहसास दिलाता है कि तकनीक और निजता के बीच संतुलन बनाना आज की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है।

सवाल अब भी वही है—

क्या सुरक्षा के नाम पर नागरिकों की निजी स्वतंत्रता खतरे में पड़ रही है, या यह भविष्य की आवश्यक डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत है?

एसआईआर पर संसद में दिनभर टकराव,विपक्ष की तीखी नारेबाज़ी से लोकसभा–राज्यसभा ठप, हंगामे के बीच दोपहर 2 बजे तक स्थगित हुई कार्यवाही

(जीएनएस)। नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन मंगलवार पूरी तरह एसआईआर—मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण—के विवाद से गर्म रहा। सरकारी एजेंसियों पर पक्षपात और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाने वाले विपक्ष ने सुबह से ही दोनों सदनों में घेरा डाल दिया। लगातार नारेबाज़ी और वेल में विरोध प्रदर्शन के कारण आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

सत्र की शुरुआत होते ही विपक्षी दलों ने साफ कर दिया कि वे एसआईआर मुद्दे को बिना विस्तृत चर्चा के नहीं छोड़ेंगे। उनका आरोप था कि कई राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है और इसे लेकर सरकार जवाबदेह है। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि यह पूरी तरह नियमित और संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है।

राज्यसभा में सुबह 11 बजे कामकाज शुरू हुआ, लेकिन तुरंत ही विपक्षी सांसदों ने चर्चा की मांग करते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल जारी रखने की कोशिश की, पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नियम 267 का हवाला देते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस मुद्दे को टाल रहे हैं।

वहीं, सदन के नेता जेपी नड्डा ने भरोसा दिलाया कि मंत्री रिजिजू विपक्षी नेताओं से चर्चा कर समाधान निकालेंगे। पर विपक्ष शांत नहीं हुआ। कई दलों के सदस्य—तिरुची शिवा से लेकर आरपीएन सिंह और अजीत कुमार भुयान तक—अपने-अपने मुद्दे उठाने लगे। बढ़ते शोर और लगातार अव्यवस्था के बाद सदन की कार्यवाही 11.53 बजे रोककर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।

लोकसभा का माहौल भी लगभग ऐसा ही रहा। जैसे ही कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, विपक्षी दलों ने वेल में पहुंचकर नारे लगाने शुरू कर दिए। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने बार-बार सभी दलों से शांत रहने और चर्चा में हिस्सा लेने की अपील की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने यहां तक कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलकर समाधान निकालेंगे, पर विपक्ष का रुख टस से मस नहीं हुआ।

लगातार बढ़ते शोर और नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक स्थगित की गई, फिर 12.09 बजे, और अंततः दोपहर 2 बजे तक के लिए रोक दी गई।

सत्र के केवल दूसरे दिन ही यह गतिरोध इस बात का संकेत है कि मतदाता सूची के एसआईआर मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आने वाले दिनों में और तीखी बहसें हो सकती हैं। देश में चुनावी तैयारियों के बीच इस विवाद ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है।

बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव चरम पर: पूर्व PM खालिदा ज़िया की हालत गंभीर, अस्पताल के बाहर सुरक्षा कड़ी

(जीएनएस)। ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख बेगम खालिदा ज़िया की बिगड़ती सेहत ने देश की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोनों को गंभीर चिंता में डाल दिया है। 23 नवंबर को ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती की गई 79 वर्षीय नेता पिछले कई दिनों से सीसीयू में जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। 27 नवंबर को उनकी हालत अचानक गंभीर हुई, जिसके बाद उन्हें चौथी मंजिल के विशेष वीवीआईपी ज़ोन में शिफ्ट कर दिया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि दवाओं का असर बेहद धीमा है और उनके कई अंगों पर दबाव बढ़ रहा है। अस्पताल के बाहर का माहौल अब पूरी तरह सुरक्षा में घिरा हुआ है। सोमवार सुबह तड़के ही ढाका पुलिस और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की अतिरिक्त टीमें एवरकेयर अस्पताल पहुँचीं और चौथी मंजिल का पूरा इलाक़ा खाली कराया गया। किसी भी आम व्यक्ति को उस मंज़िल की ओर बढ़ने की अनुमति नहीं है। अस्पताल प्रशासन ने साफ कहा है कि खालिदा ज़िया अत्यंत संवेदनशील चिकित्सा स्थिति में हैं और हर मिनट उनकी निगरानी की

जा रही है।

डॉ. एजेएम ज़ाहिद हुसैन, जो लंबे समय से उनके व्यक्तिगत चिकित्सक हैं, ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में खालिदा ज़िया की स्वास्थ्य स्थिति में कोई स्पष्ट सुधार नहीं आया है। मेडिकल बोर्ड अब उस संभावना पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि क्या वर्तमान परिस्थिति में उन्हें विदेश ले जाकर उन्नत उपचार दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा निर्णय उनकी नाज़ुक स्थिति को देखते हुए काफी जटिल है। उधर, लंदन में निर्वासन झेल रहे उनके बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारेक रहमान लगातार अस्पताल प्रशासन और परिवार से संपर्क में हैं। उन्होंने समर्थकों और शुभचिंतकों द्वारा मां के लिए की जा रही दुआओं का आभार व्यक्त किया और संकेत दिया कि परिस्थितियाँ बिगड़ती रहीं तो वे बांग्लादेश लौटने पर विचार कर सकते हैं।

स्थिति ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर संदेश जारी कर खालिदा ज़िया के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए यह भी कहा कि भारत हर संभव चिकित्सा सहयोग देने को तैयार है। दक्षिण एशियाई कूटनीति में खालिदा जिया का प्रभाव लंबे समय से रहा है, ऐसे में उनकी बिगड़ती हालत क्षेत्रीय राजनीतिक हलकों में चिंता का कारण बन गई है।

बीएनपी उपाध्यक्ष अहमद आज़म ख़ान ने प्रोथोम आलो से कहा कि हालात "बेहद नाज़ुक" हैं और रविवार रात से किसी प्रकार का सुधार दिखाई नहीं दिया है। ब्रिटेन के वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम भी ढाका पहुँच चुकी है, जो अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के साथ मिलकर आगे के उपचार की सलाह देगी। बीएनपी नेताओं ने समर्थकों से प्रार्थना जारी रखने, शांत रहने और भ्रामक सूचनाओं से बचने की अपील की है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक आने वाले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक, सबकी निगाहें एवरकेयर अस्पताल की चौथी मंजिल पर टिकी हैं, जहाँ बांग्लादेश की राजनीति की सबसे सशक्त आवाज़ों में से एक—बेगम खालिदा ज़िया—ज़िंदगी से जूझ रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या घुसपैठियों पर कड़ा रुख: 'क्या हम रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करें?'

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या घुसपैठियों की हिरासत में कथित गायब होने के मामले में सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या अवैध घुसपैठियों के लिए 'रेड कार्पेट' बिछाकर स्वागत किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यह सवाल तब उठाया जब याचिकाकर्ता ने अदालत को अवगत कराया कि मई महीने में दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्या घुसपैठियों को हिरासत में लिया था और तब से उनका कोई पता नहीं है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिरासत में रखे गए घुसपैठियों के गायब होने के पीछे प्रशासन की लापरवाही है और उन्हें कानून के तहत वापस भेजा जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने वाले रोहिंग्या घुसपैठियों को सरकार द्वारा शरणार्थी का दर्जा दिया गया है या नहीं, यह महत्वपूर्ण सवाल है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी पूछा कि इन घुसपैठियों को खाद्य, आवास और बच्चों की शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना उचित है या नहीं, जबकि देश में अनेक गरीब और वंचित नागरिक अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता से स्पष्ट किया कि क्या अवैध घुसपैठियों को विशेष सुविधाएं देकर स्थानीय नागरिकों के अधिकारों पर असर डाला जाना चाहिए।

याचिका रीता मनचंदा द्वारा दायर की गई है, जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया है कि रोहिंग्या घुसपैठियों को उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार देश से वापस भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील बताते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ और शरणार्थी मुद्दों में राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक कल्याण दोनों पक्षों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह सुनवाई केवल रोहिंग्या घुसपैठियों की कानूनी स्थिति का मामला नहीं है, बल्कि इससे देश की शरणार्थी नीति, नागरिक अधिकार और सुरक्षा ढांचे पर बहस छिड़ सकती है। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देना या विशेष सुविधाएं देना संविधान और कानून के दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जाएगा।

आगामी 16 दिसंबर को इस याचिका की अगली सुनवाई में अदालत से उम्मीद की जा रही है कि घुसपैठियों की हिरासत, उनकी वापसी और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इस सुनवाई से न केवल रोहिंग्या घुसपैठियों की स्थिति पर स्पष्टता आएगी, बल्कि भविष्य में अवैध प्रवासन और शरणार्थी मामलों के लिए भी निर्णायक मिसाल कायम होगी।

अमेज़न नदी में त्रासदी,अचानक आए भूस्खलन से दो नावें टकराकर डूबीं, पेरू के उकायाली क्षेत्र में 12 की मौत-दर्जनों लापता, बचाव अभियान तेज

(जीएनएस)। लीमा। पेरू के अमेज़न बेसिन में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली त्रासदी सामने आई, जब उकायाली नदी क्षेत्र में अचानक भारी भूस्खलन हुआ और तेज धारा में बहते मलबे ने दो यात्री नावों को आपस में टकरा दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों नावें देखते ही देखते नदी में समा गईं। हादसे में तीन बच्चों समेत कम से कम 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 50 से अधिक लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। नदी की उग्र धार और फिसलन भरी मिट्टी के कारण राहत कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है।

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, दुर्घटना सुबह उस समय हुई जब दोनों नावें उकायाली की मुख्य धारा में आमने-सामने की दिशा से आ रही थीं। ठीक उसी दौरान पहाड़ी ढलान का एक बड़ा हिस्सा भूस्खलन के साथ नदी में गिरा और अचानक बने तेज प्रवाह ने नावों का संतुलन बिगाड़ दिया। ग्राउंड न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट में अमेरिकी समाचार एजेंसी के हवाले से बताया गया कि नावों पर कई आदिवासी परिवारों के सदस्य और चिकित्सक सवार थे, जो नदी के किनारे बसे दूरस्थ गांवों की ओर जा रहे थे।

पेरू की राष्ट्रीय पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि अब तक 12 शव बरामद किए जा चुके हैं और नदी में लापता यात्रियों की तलाश जारी है। कई लोगों के तेज धारा में बह जाने की आशंका है। राष्ट्रीय आपात प्रतिक्रिया केंद्र (COEN) ने बताया कि बचाव अभियान में एक हेलिकॉप्टर, गोताखोरों की टीमें और स्निफर डॉग्स को शामिल किया गया है। नदी के आसपास आदिवासी समुदाय भी स्थानीय स्तर पर खोज में मदद कर रहे हैं।

राहतकर्मियों ने कहा कि नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर और भूस्खलन के बाद फैला मलबा उनके काम को बेहद मुश्किल बना रहा है। कई क्षेत्रों तक नौकाएँ पहुँच नहीं पा रहीं, जिससे लापता लोगों तक पहुंचने में देरी हो रही है। उकायाली क्षेत्र में बारिश पिछले कई दिनों से जारी है और विशेषज्ञों का मानना है कि अधिक जलभराव की वजह से पहाड़ी ढलानों की मिट्टी ढीली पड़ गई, जिसके चलते यह बड़ा भूस्खलन हुआ।

स्थानीय आदिवासी संगठनों ने सरकार से तत्काल अतिरिक्त सहायता भेजने की अपील की है। उनका कहना है कि इस इलाके में नदी ही परिवहन का मुख्य साधन है, इसलिए नावों की सुरक्षा और मौसम चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। वहीं पेरू सरकार ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और सभी पीड़ित परिवारों को आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया है। अमेज़न नदी के इस दूरस्थ हिस्से में हुई यह दुर्घटना उस क्षेत्र की कठोर भौगोलिक परिस्थितियों और अस्थिर जलवायु परिस्थितियों की याद दिलाती है, जहाँ कई समुदाय रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इसी नदी पर निर्भर हैं। लेकिन इसी नदी की अनिश्चित धारा कभी-कभी भारी त्रासदी भी लेकर आती है—जैसे सोमवार सुबह आई यह दिल दहला देने वाली घटना, जिसने उकायाली के जंगलों में गहरा मौन छोड़ दिया।

गरवी गुजरात हिन्दी

JioTV CHENNAL NO. 2002

Jio Air Fiber · Jio Tv + · Jio Fiber · Daily Hunt · ebaba Tv · Dish Plus

DTH live OTT · Rock TV · Airtel · Amezone Fire · Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

एसआईआर के सवाल

निस्संदेह, किसी लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष होनी चाहिए। साथ ही मतदाताओं की विश्वसनीयता भी उतनी जरूरी है ताकि वाजिब वोट ही चुनाव प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाए। इसी आलोक में नौ राज्यों व तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल तार्किक समाधान मांगते हैं। इस प्रक्रिया में तुरत-फुरत की कार्यनीति के चलते कई राज्यों में अफरा-तफरी का आलम नजर आता है। जिसका दबाव जमीनी स्तर पर इस प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर पड़ रहा है। कई बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ बेहद तनाव में नजर आ रहे हैं। इनका कार्य मतदाता सूचियों को अपडेट करना है। पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में कम समय में अधिक काम के दबाव के चलते कुछ बीएलओ के मरने व आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं। आरोप है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों द्वारा भी उन्हें परेशान किए जाने का आरोप है। हालांकि, इस अव्यवस्था के चलते ही चुनाव आयोग ने अब एसआईआर के कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। लेकिन कहना कठिन है कि इस कदम से बीएलओ का तनाव कम करने या विभिन्न हितधारकों की आशंकाओं को दूर करने में कोई खास मदद मिल सकेगी। कहा जा रहा है कि एक माह पहले शुरू हुई राष्ट्रव्यापी एसआईआर प्रक्रिया में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। इस प्रक्रिया में करीब 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं, जो तकरीबन भारतीय आबादी का एक-तिहाई से भी ज्यादा। उनकी शिनाख्त से जुड़ी जानकारी को एक निश्चित समय सीमा में प्रमाणित कर पाना आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि निर्धारित समय-सीमा व्यावहारिक नहीं है। तीन महीने की अवधि में गणना प्रपत्रों का वितरण, उसके बाद मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन और फिर अंतिम मतदाता सूची जारी करना आसान काम नहीं है। बहुत तेजी से काम को अंजाम देने का जिम्मा अधिकारियों पर अतिरिक्त दबाव बना रहा है।

निस्संदेह, स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का शुद्धीकरण एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन महत्वपूर्ण काम को जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। मतदाता को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय मिले ताकि उनके नाम सूचियों में सही ढंग से दर्ज हो सकें। यही बात बीएलओ के लिए भी लागू होती है, ताकि वे अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहराव वाले मतदाताओं का डेटा संकलित करने के लिए बूथ-स्तरीय एजेंटों के साथ मिलकर सुचारु रूप से काम कर सकें। यदि एसआईआर की प्रक्रिया किसी विवाद में उलझी रहती है तो इस अभियान का उद्देश्य ही विफल हो सकता है। बिहार की एसआईआर प्रक्रिया के घटनाक्रमों से मिले सबक को अन्य राज्यों में इस प्रक्रिया के दौरान याद रखा जाना चाहिए। निस्संदेह, स्तरहीन व संदिग्ध एसआईआर हमारे चुनावी लोकतंत्र की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचा सकता है। उल्लेखनीय है कि विशेष गहन पुनरीक्षण की यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों तथा अंडमान-निकोबार, लक्ष्यद्वीप व पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेशों में जारी है। उल्लेखनीय है कि जहां बीएलओ पर कार्यदबाव व समय सीमा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं कई राज्यों में बीएलओ के खिलाफ मामले दर्ज करने के भी आरोप लगे हैं। इन अधिकारियों का आरोप है कि अतिरिक्त कार्य-दबाव का उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। वहीं चुनाव आयोग का आरोप है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते प्रक्रिया की निष्पक्षता व पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। वैसे यदि वास्तव में बीएलओ पर अतिरिक्त दबाव है तो चुनाव आयोग को इस मुद्दे का समाधान संवेदनशील ढंग से करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मतदाता पहचान से जुड़े प्रमाणपत्रों को जुटाने में आ रही परेशानियों के चलते लोग भी बीएलओ पर दबाव बनाते हैं। कई राज्यों में बीएलओ संगठनों ने प्रदर्शन करके अधिक समय दिए जाने की मांग भी की है। कुछ लोग चुनाव आयोग की जल्दबाजी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि दो-तीन महीने का काम एक माह में पूरा नहीं किया जा सकता। वे समय पर दायित्व न निभा पाने वाले बीएलओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अनुचित बताते हैं।

लाल किला विस्फोट से उठे कुछ सवाल और सबक

> दिल्ली में लाल किला बम विस्फोट मामला दिल दहलाने वाला है। हालांकि जम्मू-कश्मीर पुलिस के यत्नों से फरीदाबाद में विस्फोटक का जखीरा पकड़ा गया जिससे भारी तबाही टल गयी। ऐसी घटनाएं टालने को हमें अपने पुलिस थानों के नेटवर्क को और मजबूत करना होगा क्योंकि वे हमारे सुरक्षा तंत्र की मुख्य धुरी हैं। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीतिक एकजुटता भी जरूरी है।

नई दिल्ली में हुए कार विस्फोट को कुछ अर्सा बीत चुका है। काफी वक्त बीत चुका और जांच ने रफ़्तार एवं दिशा पकड़ ली है। हमले संबंधी अलग-अलग थ्योरियों को समझाने और खुलासे करने के लिए इतना समय पर्याप्त है। लाल किले के गेट के पास हुआ विस्फोट दहलाने वाला और धृष्टता रोंगटे खड़े करने वाली थी।

जो बात एकदम दिमाग में आती है वह यह है कि योजनाएं लंबे समय से बन रही होंगी; प्रोफेशनल्स (अधिकतर डॉक्टर) को इसे अंजाम देने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया गया, और इसमें काफी समय लगता है। उच्च-स्तरीय विस्फोटक बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा की गई, आसानी से उपलब्ध कैमिकल से बम बनाने का बढ़िया प्रशिक्षण दिया गया (यह फिल्मों में दिखाए जाने वाले काम जितना आसान नहीं,बल्कि इसके लिए बहुत कौशल चाहिए)। टार्गेट चुने गए, रेकी की गई और एक साथ कई इलाकों में बड़े पैमाने के हमले करने के लिए इस जाल के सब धागों के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया।

ऐसा लगता है कि इस बार हमारी पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह बेखबर थीं और एक बहुत खतरनाक दुश्मन संगठन के मंसूबों और गतिविधियों को पकड़ नहीं पाईं। यह सिर्फ जम्मू एवं कश्मीर पुलिस की कारगुजारी रही, जिसने भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा, जिससे आगे चलकर आतंकवादियों के एक जटिल और बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ और दिल्ली एवं अन्य जगहों पर तबाही मचाने की उनकी नापाक योजना का पता चल सका। ऐसा लगता है कि ये आतंकवादी तुर्की और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहे थे। गतिविधियों का केंद्र फरीदाबाद स्थित अल फलाह मेडिकल कॉलेज लगता है, और कथित तौर पर इसका

उद्गम स्थल कश्मीर है। कतिपय कारणों से, प्रशासन में बैठे लोग जम्मू-कश्मीर से स्थानीय आतंकवादियों का सफाया कर दिए जाने का दावा करते रहते हैं। जाहिर है, इस हमले से उनके दावे की कलई खुल गई और इस सिलसिले में आयेदिन जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इत्यादि में नए खुलासे, नई धरपकड़ एवं गिरफ्तारियां हो रही हैं। जाहिर है, पकड़े गए लोगों से पूछताछ ही इन हिरासतों और बरामदगी का आधार है।

मुझे इस बात की चिंता है कि प्रथम विचार से लेकर लोगों को प्रशिक्षित करने तक, सामग्री खरीदना, टार्गेट चुनना और लोगों एवं सामान की तैनाती, यह एक मुश्किल और समय लेने वाला काम है, जिसे अत्यंत गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया। ज़्यादातर काम पूरे हो चुके थे और आखिरी दांव चलने को था, लेकिन हम बहुत बड़ी तबाही देखने से बच गए... यह हमारी खुशनसीबी रही। हालांकि, यहां गौरतलब कि शुरुआती कामयाबी जम्मू-कश्मीर पुलिस के यत्नों से मिली, जिसने फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री का एक बड़ा जखीरा ढूंढ़ निकाला। बढ़िया पुलिस कारगुजारी यही होती है।

अगला स्वाभाविक प्रश्न जो साफ तौर पर उठता है वह यह कि : इस किस्म के कितने आतंकी समूह अभी भी सक्रिय हैं? उनकी संरचना और संभावित निशाने क्या हैं? इन कुकृत्यों के असली गुनहगार कौन हैं? उम्मीद है, ये प्रश्न हमारे देश के संबंधित अधिकारियों और संगठनों को चौबीसों घंटे काम करते रहने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प समझ में नहीं आता। आज, जब स्थितियां और भी ज़्यादा नाजुक हैं, तो ऐसे और हमले होने की आश्ांका हो सकती है। हमें न सिर्फ अंदरूनी तौर पर पैदा हुए आतंकियों पर नज़र रखनी है, बल्कि अपने पड़ोसियों पर भी निगाह रखनी होगी।

पाकिस्तानी हमेशा से सक्रिय रहे हैं, और अमेरिकी मदद से उनकी दुम ऊपर को उठी लगती है; हमें याद रखना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर और कुछ दूसरे राज्यों में भी, सतह के ऊपर और भूमिगत रहकर काम करने वाला उनका नेटवर्क हमेशा से रहा है। अखबार उत्तर भारत के राज्यों में हो रही विस्फोटक सामग्री की बरामदगी की खबरों से भरे पड़े हैं। इसमें बांग्लादेश से साथ बनी नई दुश्मनी और उसके साथ हमारी काफी नाजुक और खुली सीमा को जोड़ दें... तो समस्या कई गुना बढ़ जाती है। अब हमें उत्तर-पूर्व में भी अवश्य सावधान रहना होगा।

मीडिया में जो नया और हैरान करने वाला फैक्टर सामने आया है, वह है तुर्की की भागीदारी। वह जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थक रहा है, लेकिन यह पहली बार है जब यह आरोप लगा है कि आतंकवादी अपने हैंडलरों से मिलने तुर्की गए थे... इस पर ध्यानपूर्वक नज़र रखने की ज़रूरत है। मैंने जानबूझकर चीनी फैक्टर के बारे में बात करने से परहेज किया है क्योंकि हमेशा की तरह वे पड़ताल से परे और रहस्यमयी हैं, लेकिन निश्चित रूप से यह बात हमारे लिए फायदेमंद नहीं।

तो, कुल मिलाकर, जांच अब तक अच्छे नतीजे दे रही है और एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। समय रहते फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री की बरामदगी होने से हम एक बड़ी त्रासदी से बच गए हैं। हालांकि, अंदरूनी तौर पर साफ-साफ बोलना होगा, और अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए। यह केवल उच्चतम राजनीतिक एवं पेशेवर स्तर पर की गई दखल से ही संभव है। देश की सुरक्षा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं और इसे सुरक्षित रखने के लिए समय पर और बेहतरीन पुलिस कारगुजारी व खुफिया जानकारी से बेहतर कोई तरीका नहीं है। हमारे जैसे जटिल एवं विशाल मुल्क को हमेशा अंदरूनी और बाहरी, दोनों तरफ से, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनका सामना राजनयिक और सैन्य, दोनों तरह से मज़बूत बनने से हो पाएगा, क्योंकि सबसे बढ़िया जीत वो होती है जिसके लिए लड़ाई की ज़रूरत न पड़े। सन त्ज़ू ने कहा था : 'अगर आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को भी जानते हैं, तो आपको सौ लड़ाइयों के नतीजे से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद को जानते हैं लेकिन दुश्मन को नहीं, तो हर जीत के साथ आपको हार भी मिलेगी। अगर आप न तो दुश्मन को जानते हैं और न ही खुद को, तो आप हर लड़ाई में हार जाएंगे'।

इस ताकत का केंद्रबिंदु थाना स्तर की बढ़िया पुलिस कारगुजारी और खुफिया जानकारी है, जो हम इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कार्रवाई करने को प्राप्त पक्की खुफिया जानकारी।

अंदरूनी तौर पर, हमें अपने पुलिस थानों के विशाल नेटवर्क को और मज़बूत करना होगा क्योंकि वे हमारे सुरक्षा तंत्र की धुरी हैं। हमने पंजाब और जम्मू-कश्मीर में देखा है कि आतंकवाद का सबसे अच्छा जवाब एक सक्रिय और प्रेरित पुलिस बल है, क्योंकि वे धरतीपुत्र होते हैं और उन्हें अपने इलाके की भूमिगत गतिविधियों और कारकुनों का बखूबी पता होता है। जरूरत उन्हें प्रेरित करने की है, न कि उन्हें नीचा दिखाने की - यही एक अच्छे नेतृत्व की निशानी है।

यदि कहीं भाड़े के विदेशी लड़ाके हैं भी, तो भी उनकी शिनाख्त स्थानीय लोग और पुलिस आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि वे अपने इलाके के चप्पे-चप्पे को और स्थानीय लोगों को पहचानते हैं। इसके लिए पुलिस और राजनीतिक नेतृत्व, दोनों के बीच तालमेल बनाने की ज़रूरत है।

राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतें सबसे महत्वपूर्ण हैं, और यह आवश्यकता सभी दलों को इस स्थिति का सामना करने के तरीकों पर राष्ट्रीय सहमति कायम करने लायक बनाए।

प्रेरणा

विलय का क्षण: जब पार्वती का विश्वास शिव के हृदय तक पहुँचा

हर युग में, हर कथा में, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो ध्वनि की तरह नहीं, अनुभूति की तरह फैलते हैं। शिव और पार्वती की यह कहानी उसी अनुभूति का विस्तार है—इतनी गहरी, इतनी सूक्ष्म कि यह केवल पढ़ी नहीं जाती, यह भीतर उतरकर अपनी जगह बनाती है। यह उस क्षण की कथा है जब विश्वास इतना निर्मल हो गया कि दो अस्तित्वों के बीच कोई भेद बचा ही नहीं।

पार्वती जी प्रतिदिन विष्णुसहस्रनाम का पाठ करती थीं। यह उनका नियम ही नहीं, उनका तप, उनका नित्यमंत्र था। सुबह का वह समय उनका सबसे प्रिय था जब आसपास की शांति में केवल मंत्रों की मधुर लहरें गूंजती थीं, और वे उनमें पूरी तरह विलीन हो जाती थीं। वे हर नाम के साथ अपने हृदय का एक-एक कमल खिलाती जाती थीं। पर एक दिन समय की धारा थोड़ी भटक गई। कुछ कार्यों के कारण वे अपने पाठ में देर कर बैठीं। मन में हल्का-सा खिन्न भाव भी उठा कि कहीं आज उनका नियम अधूरा न रह जाए।

शिव दूर बैठे यह सब देख रहे थे। शिव की दृष्टि केवल आँखों से नहीं, आत्मा से देखती है—वे जानते थे कि पार्वती की चिंता नियम की नहीं, निष्ठा की है। तभी शिव ने सहज स्वर में कहा—"देवि, आज विष्णुसहस्रनाम का पूरा फल प्राप्त करना चाहती हो तो केवल एक बार 'राम' नाम ले लो। एक नाम तुम्हें आज हजार नामों का प्रभाव दे देगा।"

यह ऐसा वाक्य था जिसे सुनकर कोई भी साधारण मन वाला तुरंत पूछता—क्यों? कैसे? किस तर्क से? कौन-सी व्याख्या से? किस प्रमाण से? पर पार्वती ने कुछ नहीं पूछा। उनके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हुआ। उन्होंने बस शिव के वचन को सत्य मान लिया। यह वह विश्वास था जिसमें तर्क नहीं होता, केवल आत्मा की पूर्ण स्वीकृति होती है। उन्होंने एक बार हृदय से 'राम' नाम लिया, मानो अपने संपूर्ण अस्तित्व को उस एक ध्वनि में समर्पित कर दिया हो। और फिर वे अत्यंत सरलता से शिव के साथ भोजन करने बैठ गईं।

शिव के भीतर यह क्षण साधारण नहीं था। जैसे ही पार्वती ने बिना प्रश्न, बिना संदेह, बिना हिचकिचाहट के एक नाम को पूरे सहस्रनाम का स्थान दे दिया, शिव को एक गहरी प्रसन्नता ने घेर लिया। यह प्रसन्नता उस आनंद से भी ऊपर थी जिसे शब्दों में नहीं बाँधा जा सकता। यह आनंद उस विश्वास का था जो शब्द से भी सूक्ष्म होता है, और भावना से भी ऊँचा।

भोजन समाप्त होते ही शिव ने पार्वती को अचानक, अत्यंत प्रेम से अपने आलिंगन में भर लिया। यह आलिंगन कुछ क्षणों का नहीं था—यह आत्मा का आलिंगन था। उसी समय शिव ने उन्हें अपने भीतर पूरी तरह समा लिया, और वे दोनों एक ही तत्त्व बन गए। वह क्षण इतना दिव्य था कि संपूर्ण ब्रह्मांड मानो कुछ पल के लिए मौन हो गया। शिव और शक्ति फिर से एक थे—अर्धनारीश्वर।

पार्वती ने यह दिव्य परिवर्तन देखा तो उनके मन में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उन्होंने हल्के से पूछा—"स्वामी, विवाह के समय भी हमारा मिलन पूर्ण हुआ था, पर तब आपने ऐसा रूप क्यों नहीं धारण किया? आज ही आपने इस एकत्व का स्वरूप क्यों प्रकट किया?"

शिव ने उनकी आँखों में गहरे प्रेम से देखते हुए कहा—"देवि, विवाह में हम एक हुए थे, परंतु वह एकत्व विधि का था। आज तुमने जो किया, वह आत्मा का एकत्व है। विवाह के समय संस्कार थे, पर आज विश्वास है। यदि आज तुम पूछ लेती कि एक नाम हजार नामों के समान कैसे हो सकता है, तो तुममें भक्तिभाव होता, पर वह अंतिम समर्पण नहीं होता जो दो अस्तित्वों को एक बना देता है। दुनिया में हर संबंध प्रश्नों पर टिका है, पर जो संबंध विश्वास पर टिक जाए, वह स्वयं ब्रह्मांड के सत्य से जुड़ जाता है। आज तुमने प्रश्न नहीं किया—तुमने केवल विश्वास किया। और विश्वास वही कुंजी है जिससे आत्माएँ एक हो जाती हैं।"

पार्वती का हृदय इस उत्तर से भर उठा। उन्हें लगा जैसे आज उन्होंने केवल एक नाम नहीं लिया—आज उन्होंने अपने प्रेम को, अपने समर्पण को, अपने अस्तित्व को शिव के वचनों पर अर्पित कर दिया। राम नाम उनके लिए आज मंत्र नहीं रहा, बल्कि वह सेतु बन गया था—जो उन्हें शिव के अस्तित्व के भीतर तक ले गया। यह कथा केवल देवताओं का प्रसंग नहीं है, यह प्रेम का शाश्वत संकेत है। यह बताती है कि जब विश्वास इतना निर्मल हो जाए कि वह किसी प्रश्न का जन्म ही न होने दे, तब दो अस्तित्व केवल पास नहीं आते—वे एक हो जाते हैं। जब समर्पण इतना गहरा हो जाए कि उसमें तर्क की कोई जगह न बचे, तब वही समर्पण अर्धनारीश्वर का रूप धारण करता है। जहाँ विश्वास है, वहाँ दो नहीं—केवल एक सत्य है। यही उस दिव्य मिलन का रहस्य है, जो हर युग में अमर रहता है।

केंद्र सरकार की सुनियोजित रणनीति का सकारात्मक परिणाम है जीडीपी का मौजूदा उछाल!

केंद्र सरकार में पिछले लगभग 12 वर्षों से सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार की सुनियोजित आर्थिक रणनीति का सकारात्मक परिणाम जब जीडीपी के मौजूदा उछाल के रूप में सामने आया तो देश-दुनिया के आर्थिक पंडित भी चौंक गए, क्योंकि यह उनकी आकलित उम्मीदों से भी ज्यादा है। यह बात अलग है कि मोदी सरकार का लक्ष्य 4.0 सरकार बनने से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को 5 ट्रिलियन प्रदान करना है, जिस दिशा में वह मजबूती से सधे पांव रखकर अग्रसर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत की वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) में जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही, जो अर्थशास्त्रियों के 7.3-7.5% के अनुमान से कहीं अधिक अप्रत्याशित रूप से ऊंची साबित हुई। दरअसल, यह वृद्धि पिछले वर्ष की समान तिमाही के 5.6% से भी काफी बेहतर है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैः- विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और निर्माण क्षेत्र में 8.1% तथा सेवा क्षेत्र में 9.2% की मजबूत वृद्धि ने इस अप्रत्याशित तेजी को संभव बनाया। इसके अलावा, जीएसटी दरों में कटौती, त्योहारों से पहले स्टॉकिंग बढ़ना और ग्रामीण मांग में सुधार मुख्य प्रेरक बने। वहीं, अन्य सहायक कारक में निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) में 7.9% की वृद्धि से उपभोक्ता खर्च में उछाल आया, जो आय और रोजगार वृद्धि को दर्शाता है।

यही नहीं, महंगाई दर ऐतिहासिक निचले स्तर पर आने से क्रय शक्ति मजबूत हुई, जिसमें खाद्य मूल्यों में कमी और अनुकूल बेस इफेक्ट शामिल हैं। जबकि मौद्रिक ढील, नियामक सुधारों के विलंबित प्रभाव तथा निर्यात पर सीमित असर ने भी योगदान दिया। यह प्रदर्शन अमेरिकी टैरिफ जैसे वैश्विक दबावों के बावजूद घरेलू मांग की मजबूती दिखाता है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत की जीडीपी वृद्धि के प्रमुख चालक मजबूत घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र की तेजी, सरकारी बुनियादी ढांचा निवेश और कृषि सुधार हैं। हाल की तिमाही में सेवा क्षेत्र ने 9.3% की वृद्धि दर्ज कर कुल जीडीपी को 7.8-8.2% तक खींचा। वहीं, सेवा क्षेत्र जीडीपी का 55% से अधिक योगदान देता है, जिसमें वित्तीय सेवाएं, ई-कॉमर्स और आईटी प्रमुख हैं। इसकी मजबूत वृद्धि ने खपत और रोजगार को बढ़ावा दिया। वहीं, बुनियादी ढांचा निवेश में सरकार की गतिशक्ति, भारतमाला और राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसी योजनाओं ने पूंजीगत व्यय बढ़ाया। इनसे रोजगार सृजन और निजी निवेश को गति मिली।

वहीं, कृषि और ग्रामीण मांग बढ़ी है। कृषि क्षेत्र में 3.7% वृद्धि और सामान्य मानसून ने ग्रामीण खपत को समर्थन दिया। यह 15-18% जीडीपी योगदान के साथ 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। अन्य सुधार जैसे- पीएलआई योजना ने विनिर्माण को बढ़ावा दिया, जबकि जीएसटी और कॉर्पोरेट कर सुधारों ने व्यापार वातावरण सुधारा। जबकि आत्मनिर्भर भारत ने नवाचार और निर्यात को प्रोत्साहित किया।

जानकार बताते हैं कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र में हालिया वृद्धि (जैसे जुलाई 2025 में 5.4% और Q2 FY26 में मजबूत उत्पादन) के प्रमुख कारण मजबूत घरेलू मांग, नए ऑर्डरों का उछाल तथा जीएसटी दर कटौती रहे। क्षमता उपयोग 75% तक पहुंचा, जिससे 87% इकाइयों ने उच्च उत्पादन दर्ज किया। वहीं घरेलू मांग में बढ़ोतरी हुई। घरेलू बाजारों से ऑर्डर बुक में वृद्धि हुई, विशेषकर ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन टूल्स और धातु क्षेत्रों में। 83% निर्माताओं को आने वाले महीनों में अधिक ऑर्डर की उम्मीद है। नीतिगत समर्थन जैसे- पीएलआई योजना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने निवेश आकर्षित किया, जबकि 50% से अधिक इकाइयां क्षमता विस्तार की योजना बना रही हैं। वहीं बुनियादी ढांचा सुधारों ने लागत कम की। उत्पादन विस्तार यानी नए ऑर्डरों से इनपुट खरीद और कार्यबल वृद्धि हुई, जो पांच वर्षों की सबसे तेज वृद्धि दर्शाती है। वहीं निर्यात स्थिरता ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाई।

अर्थशास्त्री बताते हैं कि भारत के सेवा क्षेत्र में हालिया वृद्धि (जैसे जून 2025 में PMI 60.4 तक पहुंचना) के प्रमुख कारण घरेलू एवं निर्यात मांग में तेजी, नए ऑर्डरों का उछाल तथा डिजिटल सेवाओं का विस्तार रहे। कोविड के बाद वित्तीय, आईटी और प्रोफेशनल सेवाओं ने समग्र जीवीए वृद्धि को पीछे छोड़ा। मांग वृद्धि हुई। घरेलू बाजारों के साथ एशिया, मध्य पूर्व एवं अमेरिका से निर्यात मांग में उल्लेखनीय तेजी आई, जो नए कारोबार को बढ़ावा दे रही।वहीं, आय स्तर बढ़ने से पर्यटन, ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन सेवाओं की मांग बढ़ी। डिजिटल परिवर्तन यथा-ऑनलाइन भुगतान, ई-कॉमर्स एवं उच्च तकनीक सेवाओं की ओर तेज संक्रमण ने उत्पादकता बढ़ाई। वहीं, नीतिगत सुधारों एवं बेहतर आधारभूत संरचना ने 55% जीडीपी योगदान को मजबूत किया। रोजगार एवं लागत लाभ बढ़े।लगातार 37 महीनों से रोजगार सृजन जारी रहा, जबकि इनपुट लागत 10 महीनों के निचले स्तर पर पहुंची। इससे कंपोजिट PMI 61.0 तक मजबूत हुआ।

जानकारों का यह भी कहना है कि आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में वृद्धि के प्रमुख कारण भारत में बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश, विशेष रूप से राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (NIP) कार्यक्रम द्वारा, हैं जो ऊर्जा, सड़क, रेलवे, शहरी विकास और अन्य क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देता है।

अभियान

चमत्कारों का पावन मार्ग: पाँच दिव्य मंदिर जहाँ पहुँचते ही बदल जाती है भक्त की किस्मत

भारत की मिट्टी में केवल इतिहास ही नहीं, आस्था की वह जीवित धारा भी बहती है जो हर जनमानस को अपने साथ जोड़ लेती है। इस देश में मंदिर पत्थरों की इमारतें नहीं, बल्कि दिव्यता की साँस हैं। हर प्रदेश, हर गाँव, हर नदी के किनारे कोई न कोई ऐसा पवित्र स्थान मिल ही जाता है जहाँ पहुँचते ही मन अपने आप झुक जाता है और जीवन नया प्रकाश पा लेता है। अनेक मंदिर ऐसे हैं जहाँ दर्शन मात्र से ही कष्ट दूर होने का विश्वास सदियों से चला आ रहा है। इन स्मृतियों में, इन अनुभवों में, इन कथाओं में वह शक्ति छिपी है जो भक्त के कदमों को स्वयं उस धाम तक ले जाती है जहाँ मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं और जीवन नए रंग में ढलता है।

भारत के पाँच ऐसे दिव्य मंदिरों की यात्रा इसी भावना की कथा है—जहाँ न केवल पूजा होती है, बल्कि श्रद्धा की प्रतिध्वनि आकाश तक गूंजती है। जहाँ लोग खाली हाथ जाते हैं, और आशा से भरे मन के साथ लौटते हैं। जहाँ कष्टों का अंत होता है और जीवन में शांति का आरंभ।

सबसे पहले आते हैं काशी विश्वनाथ—जहाँ शिव स्वयं काशी की धूल में वास करते हैं। वाराणसी की संकरी गलियों से गुजरते हुए जब भक्त गंगा तट पर पहुँचे ज्योतिर्लिंग के सामने खड़ा होता है, तो लगता है मानो समय थम गया हो। काशी केवल एक शहर नहीं, शिव का वह शाश्वत मंडल है जहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। ऐसी मान्यता है कि एक बार यदि कोई जातक वहाँ शिव का दर्शन कर ले, तो उसके जीवन के सभी कष्ट, पाप, बाधाएँ और दुःख गंगा की धारा में बह जाते हैं। सावन के महीने में जब पूरे नगर में त्रिपुंड, रुद्राक्ष और 'हर-हर महादेव' की ध्वनि गूँजती है, तो लगता है कि स्वयं शिव ने अपनी जटाओं को खोल दिया हो। यहाँ दर्शन मात्र से मनोकामनाओं के पूर्ण होने का विश्वास सदियों से जीवित है।

दूसरा धाम है तिरुपति बालाजी—भारत का वह आकाशमंदिर जो तिरुमला पर्वत की ऊँचाइयों पर स्थित है। यह केवल एक मंदिर नहीं, ईश्वर के प्रति अर्पण का सर्वोच्च स्थान है। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पहुँचकर भक्त अपने जीवन के दुःखों का बोझ भूल जाता है। कहा जाता है कि बालाजी एक ऐसी शक्ति हैं जो भक्त की हर मनोकामना को सुनते नहीं, बल्कि अनुभव करते हैं। इसी कारण यहाँ लाखों भक्त अपने बाल अर्पित करते हैं—यह संकेत है अपने अहंकार, अपनी वासनाओं, अपने संदेहों और अपने बोझ को परमात्मा को सौंप देने का। तिरुपति में आने वाला भक्त हल्का होकर लौटता है, मानो ईश्वर ने उसके हृदय से सारे भय निकाल दिए हों।

इसके बाद है महाराष्ट्र का शिरडी—जहाँ साईं बाबा के नाम में वह ममता, वह करुणा है जो जीवन के हर अंधेरे को मिटा देती है। शिरडी पहुँचते ही लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर आशीर्वाद रख देता है। साईं बाबा ने धर्म का भेद मिटाकर हर मनुष्य को प्रेम, समानता और सेवा का मार्ग दिखाया। यहाँ आने वाले हजारों भक्त कहते हैं कि बाबा उनकी पीड़ा को अपने ऊपर ले लेते हैं और मन में ऐसी शांति उतरती है जैसी किसी को माँ की गोद में मिलती है। शिरडी का मार्ग भक्त को अंदर से बदल देता है—वह दर्द कम नहीं करता, बल्कि उसे सहने की शक्ति देता है।

राजस्थान का खाटू श्याम अगला पावन स्थान है—वह वीर बर्बरीक जिनका बल, त्याग और भक्ति उन्हें कलियुग के 'श्याम' रूप में जीवित रखती है। खाटू श्याम का मंदिर केवल इच्छा पूर्ण करने का केंद्र नहीं, बल्कि आशा का घर है। भक्त जब श्याम बाबा के दरबार में 'हारे का सहारा' कहकर नतमस्तक होता है, तो उसके जीवन की उलझनें जैसे स्वयं खुलने लगती हैं। यहाँ का श्याम कुंड भी अत्यंत चमत्कारी माना जाता है—इसमें स्नान करने से मनोकामनाएँ सिद्ध होती हैं और जीवन की अड़चनें दूर होती हैं। खाटू पहुँचकर भक्त के चेहरे पर जो चमक आती है, वह केवल श्रद्धा का नहीं, आत्मिक शांति का प्रकाश होता है।

और अंत में है माता वैष्णो देवी का त्रिकूट पर्वत—जहाँ पहुँचने के लिए एक कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। यह कठिनाई ही यात्रा का सौंदर्य है, क्योंकि माना जाता है कि माँ अपने भक्त को उतना ही पास बुलाती हैं जितना वह सहन कर सके। कटरा से लेकर भवन तक का हर कदम एक तपस्या की तरह है। जब भक्त 'जय माता दी' का उद्घोष करते हुए माता के दरबार में पहुँचता है, तो उस क्षण उसे लगता है कि उसकी सारी थकान, सारे दुःख, सारी पीड़ा माँ की चरणधूलि में समा गई। माता वैष्णो केवल मनोकामनाएँ पूर्ण नहीं करतीं—वह जीवन को दिशा देती हैं और साधक को नया संबल प्रदान करती हैं।

इन पाँचों मंदिरों में एक अनोखी समानता है—दर्शन होते ही मन बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, जीवन बदल जाता है। यहाँ प्रसाद भले ही मिठाई हो, पर सबसे बड़ा प्रसाद शांति है। यहाँ पाँव भले ही पत्थरों पर चलते हों, पर आत्मा आकाश में उड़ती है। यहाँ लोग मांगने आते हैं, पर अक्सर पाते उससे ज्यादा हैं जितना उन्होंने सोचा भी नहीं होता।

भारत की यही आस्था है—अनंत, अगाध, अटूट। यह कहानियों में नहीं, अनुभवों में जीवित है। और इन अनुभवों में ईश्वर केवल मूर्ति में नहीं, बल्कि भक्त के विश्वास में बसता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

पुतिन की भारत यात्रा: रक्षा, परमाणु ऊर्जा और द्विपक्षीय व्यापार में बड़े समझौतों की संभावना

(जीएनएस)। नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की भारत यात्रा को लेकर देश में राजनीतिक और कूटनीतिक उत्साह चरम पर है। इस दौरे के दौरान रक्षा, ऊर्जा और व्यापारिक सहयोग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस यात्रा के एजेंडे में पांचवीं पीढ़ी के सुखोई-57 लड़ाकू विमानों की खरीद, एस-400 लंबी दूरी की हवाई सुरक्षा प्रणाली का सौदा, जेट इंजन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और भारत में छोटे परमाणु संयंत्रों की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने और द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए भी दोनों देशों के अधिकारी किसी साझा फार्मूले पर सहमति बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंध केवल औपचारिक समझौतों तक सीमित नहीं हैं। यह साझेदारी ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच विकसित हुई है और इसमें वैश्विक मामलों में साझा दृष्टिकोण, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान और सुरक्षा सहयोग शामिल है। पेस्कोव ने कहा कि रूस गर्व के साथ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहा है। उनके अनुसार पुतिन की यात्रा के दौरान रक्षा, ऊर्जा और उच्च तकनीक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है, जो दोनों देशों के

रणनीतिक हितों को मजबूत करेंगे और द्विपक्षीय साझेदारी को नई ऊँचाइयों तक ले जाएंगे।

रक्षा क्षेत्र में इस यात्रा के दौरान विशेष चर्चा सुखोई-57 स्टेल्थ फाइटर विमानों और एस-400 लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली पर होने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार यह समझौते भारत की वायु और हवाई सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेंगे। इसके अलावा रूस की भागीदारी भारत में छोटे परमाणु रिएक्टरों की स्थापना और कुडनकुलम में असैन्य परमाणु संयंत्र परियोजनाओं में जारी रहेगी। पेस्कोव ने कहा कि रूस के पास छोटे और लचीले रिएक्टरों का व्यापक अनुभव है, जो भारत के भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। व्यापारिक और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में भी इस यात्रा को अहम माना जा रहा है। पेस्कोव ने बताया कि अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत-रूस के द्विपक्षीय व्यापार पर प्रभाव पड़ा है, और इसे कम करने के लिए दोनों देशों के अधिकारी व्यापारिक ढांचे में सुधार और बदलाव के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश द्विपक्षीय व्यापार अब राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहा है, जिससे लेनदेन सुरक्षित और स्थिर बना हुआ है। इससे न केवल आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा, बल्कि व्यापारिक निर्भरता में भी स्थायित्व आएगा।

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में पेस्कोव ने रूस-यूक्रेन युद्ध और आतंकवाद के मुद्दों पर भी अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने कहा कि रूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का सम्मान करता है और युद्ध के समाधान के लिए अमेरिका की योजना का भी समर्थन करता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग अति आवश्यक है। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में हुए विस्फोटों की निंदा करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर मिलकर इस खतरे को कम किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन की यह यात्रा न केवल रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में नए सौदों को गति देगी, बल्कि भारत और रूस के लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को भी नई दिशा देगी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग, रक्षा उत्पादन, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों में गहराई लाने के लिहाज से निर्णायक सिद्ध हो सकती है। इससे भारत को अपने सामरिक हितों को सुरक्षित करने और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, जबकि रूस को भारतीय बाजार और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

पुतिन की भारत यात्रा को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में यह उम्मीद जताई जा रही है कि समझौतों की घोषणा से दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी और आने वाले वर्षों में रक्षा, ऊर्जा और व्यापारिक क्षेत्र में व्यापक सहयोग की संभावनाएँ बढ़ेंगी। इस दौरे के परिणामों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और तकनीकी सहयोग के कई पहलुओं पर प्रभाव डाल सकता है।

अहमदाबाद मंडल ने नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 800 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त किया

राजस्व में 15.88% की ऐतिहासिक वृद्धि, माल ढुलाई राजस्व में सर्वकालिक उच्च स्तर पर

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने नवंबर 2025 उत्कृष्ठ प्रदर्शन करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंडल ने नवंबर 2025 में 806.68 करोड़ का कुल राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष के इसी महीने के प्रदर्शन से 15.88% अधिक है।

नवंबर 2025 की उपलब्धियां

- सर्वश्रेष्ठ माल ढुलाई राजस्वः मंडल ने 628.68 करोड़ का शानदार माल ढुलाई राजस्व (Goods Revenue) अर्जित किया। यह इस वित्तीय वर्ष नवंबर 2025 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जो नवंबर 2024 के माल ढुलाई राजस्व 554.65 से 13.35% अधिक है।
- यात्री राजस्व में वृद्धिः नवंबर 2025 में मंडल से 34.90 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जिससे 152.59 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जो गतवर्ष 125.28 करोड़ की तुलना में 21.80% की उल्लेखनीय वृद्धि है।
- OCH (अन्य कोचिंग राजस्व) में महत्वपूर्ण उछालः अन्य कोचिंग (OCH) राजस्व 25.50 करोड़ रहा, जो गतवर्ष नवंबर 2024 के ओसीएच राजस्व 16.20 करोड़ से 57.41% अधिक है।

- टिकट जाँच राजस्वः टिकट जाँच राजस्व में भी सुधार हुआ, जो 2.43 करोड़ तक पहुँच गया, जो गतवर्ष के 1.82 करोड़ से 33.52% अधिक है।

BDU (बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट) के प्रयासः

बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (BDU) के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप, पाँच माल ढुलाई टर्मिनलों ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ मासिक माल ढुलाई राजस्व दर्ज कियाः

- चंडीसर (ATGC) में मेसर्स अल्फा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड का जीसीटीः 3.36 करोड़।
- मेसर्स नवकार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NCLW) का जीसीटीः 10.43 करोड़।
- मेसर्स कॉन्टिनेंटल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (CWCJ) न्हावा शेवाः 5.29 करोड़।
- सणोसरा माल टर्मिनल (SNSR): 9.62 करोड़।
- शिरवा माल टर्मिनल (SRVA): 11.37 करोड़।

नए यातायात स्ट्रीम और नवाचार

- नया उत्पाद (New Commodity): पहली बार डेडिकेटेड रेफ्रिजरेटेड "रीफर" कंटेनर रैक को सफलतापूर्वक MHPL-साणंद से पिपावाव पोर्ट के लिए लोड और रवाना किया गया, जिससे 6.57 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।
- नया शुरुआती बिंदु (New Originating Point): गांधीधाम (GIMB) से आज़रा (AZA), एनएफ रेलवे के लिए मिश्रित वस्तुओं का एक नया रैक लोड किया गया, जिससे 85.75 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।

नए कस्टमर और राजस्वः

- औद्योगिक नमक के चार रेक सनोसरा से नागदा और गढ़वा रोड प्राइवेट साइडिंग के लिए लोड किए गए, जिससे 2.34 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।
- एनपीके उर्वरकों के बारह रेक कांडला पोर्ट और कांडला पोर्ट डॉक रेल टर्मिनल से छह-छह रेक लोड किए गए, जिससे 5.30 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

बेंटोनाइट के दो रेक को BOST वैगनों में सनोसरा से रंगाली, पूर्व तटीय रेलवे तथा करिगनूरू, दक्षिण पश्चिम रेलवे की प्राइवेट साइडिंग के लिए लोड किया गया, जिससे 1.30 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

टिकट चेकिंग राजस्व

- अहमदाबाद स्टेशन पर तीन फोर्ट्रेस चेकिंग आयोजित की गईं, जिसमें 31 टिकट चेकिंग स्टाफ शामिल थे। इन जांचों में 657 अवैध यात्रियों के मामले पाए गए और उनसे 4.42 लाख जुर्माना वसूला गया।
- अहमदाबाद, महेसाणा, गांधीधाम, पालनपुर, साबरमती, मणिनगर और विरमगाम में आठ विशेष फोर्ट्रेस चेकिंग आयोजित की गईं, जिनमें 2015 अवैध यात्रियों के मामले पाए गए और उनसे 14.49 लाख जुर्माना वसूला गया।
- नवंबर 2025 में टिकट जांच से 2.43 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ, जो 0.33 लाख मामलों पर आधारित है। यह 2.35 करोड़ के लक्ष्य से 3.40% अधिक है।
- रेलवे परिसरों को गंदा करने वाले यात्रियों के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए, धारा 198 के तहत 349 मामलों में एंटी-लिटरिंग और एंटी-थूकने का जुर्माना वसूला गया, जिसकी राशि 0.68 लाख है।

व्यापार आउटरीच और गैर-किराया राजस्व (NFR)

- लॉजिस्टिक्स को बढ़ावाः मंडल रेल प्रबंधक (DRM) ने 27.11.2025 को कच्छ क्षेत्र में रेल लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने और माल ढुलाई की आवाजाही को मजबूत करने के लिए गांधीधाम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक बैठक की। जिसका लक्ष्य 50 मीट्रिक टन यातायात हासिल करना है।
- गैर-किराया राजस्व (NFR): नॉन-डिजिटल विज्ञापन बोर्डों और होर्डिंग्स के लिए ई-नीलामी के माध्यम से 2.10 करोड़ की संपत्ति आवंटित की गई। मेहसाणा रेलवे स्टेशन पर पार्किंग स्थल की 03 साल की अवधि के लिए ई-नीलामी 0.31 करोड़ के संविदात्मक मूल्य पर आवंटित की गई।

आईआईटी कानपुर और एनएमडीसी ने मिलाया हाथ, खनन क्षेत्र में साइबर सुरक्षा और डिजिटल नवाचार को मिलेगा नई दिशा

(जीएनएस)। कानपुर। भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थान आईआईटी कानपुर और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएमडीसी लिमिटेड ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और अत्याधुनिक तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है। इस सहयोग के तहत एनएमडीसी के आईटी और ओटी (ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी) सिस्टम्स को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए आईआईटी कानपुर की विशेषज्ञ टीम विभिन्न परियोजनाओं पर काम करेगी।

आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि संस्थान का अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और डिजिटल प्रणाली के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यह साझेदारी केवल एनएमडीसी के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि खनन क्षेत्र में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, डिजिटल ट्विन्स, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों को भी लागू किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप न केवल संचालन की दक्षता बढ़ेगी, बल्कि खनन उद्योग में नवाचार और डिजिटल सुरक्षा के नए मानक भी स्थापित होंगे।

एमओयू के तहत आईआईटी कानपुर का सी3आईहब एनएमडीसी को साइबर रिस्क असेसमेंट, सुरक्षा खामियों की पहचान, सुरक्षा प्रबंधन, घटना प्रतिक्रिया योजना (Incident Response Plan) और सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (SOC) के मॉडल को मजबूत करने में सहयोग देगा। इसके अलावा, दोनों संस्थान संयुक्त रूप से अनुसंधान परियोजनाएं चलाएंगे, तकनीकी पायलट परियोजनाओं को कार्यान्वित करेंगे और इन परिणामों को बड़े स्तर पर लागू करने की योजना भी बनाएंगे।

प्रो. अग्रवाल ने कहा कि यह सहयोग खनन उद्योग में डिजिटल नवाचार और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि आधुनिक खनन प्रक्रियाओं में डेटा सुरक्षा और तकनीकी निगरानी अत्यंत जरूरी हो गई है, क्योंकि खनन कंपनियों का संचालन अब ऑटोमेटेड सिस्टम्स और स्मार्ट मशीनों पर निर्भर करता है। इस साझेदारी के माध्यम से एनएमडीसी को न केवल साइबर हमलों से सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उत्पादन, रखरखाव और संसाधन प्रबंधन की दक्षता भी बढ़ेगी।

एनएमडीसी के अधिकारियों ने कहा कि इस एमओयू से खनन क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और शोध गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल देश में खनन उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ-साथ सुरक्षा और नवाचार के उच्च मानकों को स्थापित करने में मदद करेगी। अधिकारीयों ने बताया कि भविष्य में इस साझेदारी के तहत विकसित समाधान खनन क्षेत्र के अन्य संगठनों के लिए भी मॉडल के रूप में पेश किए जा सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि आईआईटी कानपुर और एनएमडीसी का यह सहयोग केवल एक तकनीकी समझौता नहीं है, बल्कि यह देश के खनन क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और साइबर सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक पहल है। इस कदम से खनन उद्योग में स्मार्ट टेक्नोलॉजी के व्यापक प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत में खनन संचालन अधिक सुरक्षित, दक्ष और आधुनिक बन सकेगा। इस सहयोग से यह स्पष्ट संदेश भी जाता है कि देश के सार्वजनिक और तकनीकी संस्थान मिलकर डिजिटल सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारतीय रेलवे चौथे काशी तमिल संगमम के लिए तमिलनाडु से वाराणसी के लिए सात विशेष ट्रेनें चला रहा है

(जीएनएस)। भारतीय रेलवे कन्याकुमारी, चेन्नई, कोयंबटूर और वाराणसी के बीच सात विशेष रेलगाडियों का संचालन कर रहा है ताकि चौथे काशी तमिल संगमम में बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और तमिल भाषी क्षेत्र व काशी के प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ किया जा सके। इन विशेष ट्रेनों को इस बहु-दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए निर्बाध यात्रा, आरामदायक लंबी दूरी की कनेक्टिविटी और समय पर आगमन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया है।

29 नवंबर 2025 को कन्याकुमारी से पहली ट्रेन के रवाना होने के साथ इन सेवाओं की शुरुआत हुई थी। इसके बाद आज चेन्नई से एक अतिरिक्त विशेष ट्रेन रवाना हुई। अगली प्रस्थान 3 दिसंबर को कोयंबटूर से, 6 दिसंबर को चेन्नई से, 7 दिसंबर को कन्याकुमारी से, 9 दिसंबर को कोयंबटूर से और 12 दिसंबर 2025 को चेन्नई से एक और सेवा निर्धारित है। इन नियोजित प्रस्थानों के साथ, तमिलनाडु के प्रमुख शहरों से बनारस के लिए कुल सात विशेष ट्रेनें एक सुव्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से चलेंगी।

समय पर वापसी की यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेलवे ने बनारस से कई विशेष रेलगाडियों की व्यवस्था की है। इनमें 5 दिसंबर को कन्याकुमारी, 7 दिसंबर को चेन्नई और 9 दिसंबर को कोयंबटूर के लिए ट्रेन शामिल हैं। इसके अलावा 11 दिसंबर को चेन्नई, 13 दिसंबर को कन्याकुमारी, 15 दिसंबर को कोयंबटूर और 17 दिसंबर 2025 को चेन्नई के लिए भी अतिरिक्त रेलगाडिय़ां चलेंगी।

आज से शुरू हो रहा काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण तमिलनाडु और काशी के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंध को निरंतरता देता है। यह संस्करण "आइए तमिल सीखें-तमिल करकलम" विषय पर केंद्रित है, जो वाराणसी के स्कूलों में तमिल शिक्षण पहल, काशी क्षेत्र के छात्रों के लिए तमिलनाडु के अध्ययन दौरों और तेनकाशी से काशी तक प्रतीकात्मक ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। काशी तमिल संगमम 4.0, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार को दर्शाता है जो लोगों को अपनी संस्कृति के अलावा अन्य समृद्ध संस्कृतियों को समझने और उसकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पहल शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है जिसमें आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रमुख ज्ञान भागीदार के रूप में शामलि हैं। रेलवे सहित दस मंत्रालयों की भागीदारी से, यह कार्यक्रम दोनों क्षेत्रों के छात्रों, कारीगरों, विद्वानों, आध्यात्मिक गुरुओं, शिक्षकों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ता है, जिससे उनके बीच विचारों, सांस्कृतिक विधियों और पारंपरिक ज्ञान का आदान-प्रदान सुगम होता है।

इन सात विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इस यात्रा कार्यक्रम का समन्वय कर, भारतीय रेलवे देश के विविध क्षेत्रों को जोड़ने तथा तमिलनाडु व काशी के बीच साझा विरासत को सुदृढ़ करने में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

विश्व एड्स दिवस पर भावनगर रेलवे मंडल में आयोजित हुआ व्यापक जनजागरूकता अभियान

(जीएनएस)। विश्व एड्स दिवस (World AIDS Day) के अवसर पर दिनांक 01 दिसम्बर 2025 को भावनगर रेलवे मंडल के सभी हेल्थ यूनिट्स तथा डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल, भावनगर परा में HIV/AIDS के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिक्षक श्री सुबोध कुमार के दिशा निर्देशों के अनुरूप विविध कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों में एड्स संबंधी मिथकों को दूर करना, रोकथाम की जानकारी प्रदान करना तथा स्वस्थ एवं सुरक्षित व्यवहार को प्रोत्साहित करना रहा।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि DRH BVP में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एक विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल स्टाफ द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें HIV/AIDS के कारण, प्रसार, रोकथाम तथा समाज में प्रचलित गलत धारणाओं को सरल, शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक शैली में दर्शाया गया। उपस्थित कर्मचारियों, मरीजों एवं परिजनों ने इस प्रस्तुति की अत्यंत सराहना की और जागरूकता संदेशों को आत्मसात किया। इसके अतिरिक्त अस्पताल परिसर में एचआईवी/एड्स पर स्वास्थ्य वार्ता (Health Talk), पोस्टर एवं बैनर प्रदर्शनी, रेड रिबन वितरण, IEC जागरूकता साहित्य का वितरण जैसी गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं।

भावनगर डिवीजन के धोला, जूनागढ़, जेतलसर, महुवा, पोरबंदर, गोंडल, बोटाद, धोलका, वेरावल सहित सभी हेल्थ यूनिट्स में भी विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम पूरे उत्साह से आयोजित किए गए। विभिन्न इकाइयों में पम्पलेट वितरण किया गया, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने HIV/AIDS से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की। कुछ हेल्थ यूनिट्स जैसे धोला, जेतलसर एवं जूनागढ़ ने कॉलोनी परिसर में पोस्टर डिस्प्ले व जागरूकता संदेशों का प्रसार कर अभियान को और प्रभावी बनाया।

भावनगर मंडल अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में विश्व एड्स दिवस पर आयोजित यह व्यापक जागरूकता अभियान रेलवे समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी सकारात्मक चेतना और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण प्रयास है।

ट्रेन संख्या 09086 का शॉर्ट टर्मिनेशन

(जीएनएस)। मुंबई सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर कम्प्लीट ट्रैक रिन्यूअल कार्य कार्य के लिए 60 दिनों का ब्लॉक लिया जा रहा है। इसी कारण ट्रेन संख्या 09086 का शेड्यूल इस प्रकार रहेगाः ट्रेन संख्या 09086 इंदौर – मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस बुधवार और शुक्रवार को दादर स्टेशन पर तथा रविवार को बोरीवली स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी। यह व्यवस्था आगे के आदेश तक जारी रहेगी।

पश्चिम रेलवे द्वारा महापरिनिर्वाण दिवस पर दादर स्टेशन पर सुरक्षा एवं सुविधा की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे ने भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 6 दिसंबर, 2025 को दादर स्टेशन पर बड़ी संख्या में आने वाले अनुयायियों की सुरक्षा, सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। लगभग 700 जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों को दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म, पुलों, प्रवेश–निकास द्वारों और रेलवे परिसर में चौबीसों घंटे तैनात किया जाएगा। स्टेशन पर 160 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष की 24x7 निगरानी के लिए स्टाफ तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा को उन्नत वीडियो एनालिटिक्स सुविधाओं जैसे फेस रिकग्निशन सिस्टम, पीपल डेंसिटी एनालिसिस, लेफ्ट-ओवर लगेज डिटेक्शन और लाइन-क्रॉसिंग अलर्ट आदि की सहायता से और मजबूत किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दादर स्टेशन पर आगंतुकों और चैत्यभूमि जाने वाले अनुयायियों की

सहायता के लिए 24x7 कार्यरत कई हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इन हेल्प डेस्क पर तैनात आरपीएफ, जीआरपी और टिकट जांच कर्मचारी आगंतुकों को चैत्यभूमि, राजगृह, ट्रेन समय और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए आरपीएफ डॉग स्क्वॉड, क्विक रिस्पॉन्स टीम और जीआरपी बम डिटेक्शन एंड डिस्पोज़ल स्क्वॉड (BDDS) द्वारा लगातार एंटी-सैबोटाज जांच की जाएगी। भीड़ प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम रेलवे ने बीएमसी एफओबी और तिलक एफओबी जैसे भीड़-प्रवण क्षेत्रों में बैरिकेडिंग और रस्सियों के माध्यम से सेगरेगेशन की व्यवस्था की है। प्रवेश और निकास बिंदुओं पर नियंत्रित डायवर्जन की भी व्यवस्था की गई है। सुगम आवागमन के लिए सभी पुलों और द्वारों पर स्पष्ट दिशा-सूचक संकेतक लगाए गए हैं। चिकित्सा सहायता के लिए दादर स्टेशन पर डॉक्टर, प्राथमिक उपचार और एम्बुलेंस सहित 24x7 सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। पश्चिम रेलवे के दादर स्टेशन परिसर में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है और कम रोशनी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त लाइटें लगाई गई हैं ताकि उचित दृश्यता सुनिश्चित की जा सके।

पश्चिम रेलवे सभी अनुयायियों से धैर्य बनाए रखने और अपनी यात्रा के दौरान सहयोग करने की अपील करता है। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सभी आगंतुकों को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित अनुभव सुनिश्चित करने हेतु पश्चिम रेलवे आवश्यक सुविधाएँ, समय पर मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता प्रदान करने के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है।

पूर्व एएसआई चीफ केके मुहम्मद की खास अपीलः 'ज्ञानवापी और मथुरा के मामले में मुस्लिम समुदाय पीछे हटे, हिंदू नई मांग न करें'

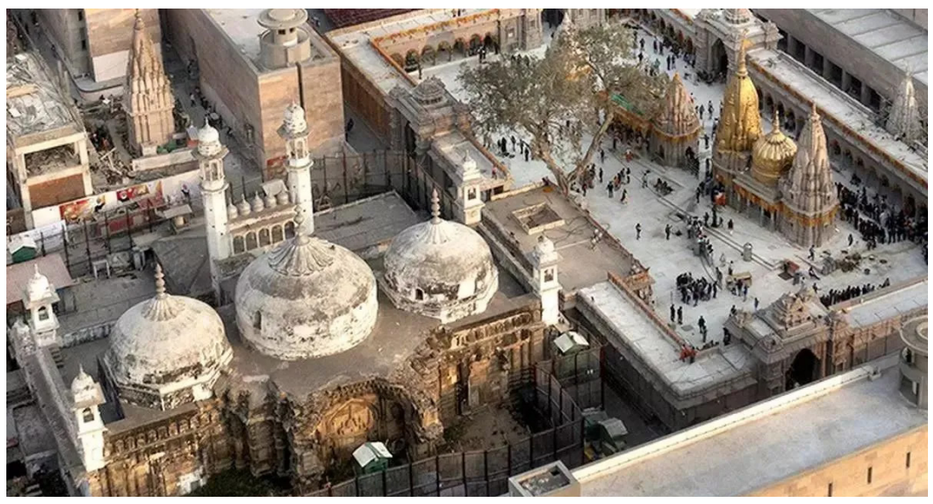

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक केके मुहम्मद ने देश में धार्मिक स्थलों को लेकर दोनों समुदायों से शांतिपूर्ण और समझौते पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को मथुरा और ज्ञानवापी जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर अपने दावे छोड़ देने चाहिए और हिंदू समुदाय को भी नई मांगों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

केके मुहम्मद ने बताया कि मथुरा भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान है और ज्ञानवापी शिव से जुड़ा है। उनका कहना है कि ये स्थल हिंदुओं के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों समुदायों को इस मामले में समझौते पर पहुंचना चाहिए ताकि धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर विवाद खत्म हो सके और भव्य हिंदू मंदिरों का निर्माण संभव हो।

पूर्व एएसआई चीफ ने स्पष्ट किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका आधार बहुसंख्यक हिंदू आबादी है। यदि यह मुस्लिम बहुसंख्यक देश होता, तो धर्मनिरपेक्षता संभव नहीं होती। उन्होंने मुस्लिम समुदाय की ओर से एक स्पष्ट इशारा देने की आवश्यकता बताई ताकि विवाद के मामलों का हल शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। इसके अलावा केके मुहम्मद ने हिंदू समुदाय को यह सुझाव भी दिया कि अयोध्या, वाराणसी और मथुरा के तीन प्रमुख धार्मिक स्थलों से आगे किसी नए स्थल को विवाद के केंद्र में न लाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराना भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक है। धर्म ध्वजा केवल एक झंडा नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता, धार्मिक चेतना और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है।

पूर्व एएसआई निदेशक केके मुहम्मद की यह अपील एक तरह से धार्मिक सौहार्द और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण की दिशा में एक गंभीर संदेश है। उनका कहना है कि विवादित स्थलों पर विवाद और दावे धार्मिक हिंसा और सामाजिक तनाव को जन्म दे सकते हैं, इसलिए समुदायों को आपसी समझ और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने दोनों पक्षों से आग्रह किया कि ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी कदम उठाया जाए ताकि सामाजिक शांति बनी रहे और धार्मिक सौहार्द कायम रहे।

चुनाव@26: BJP की तैयारी जोरों पर, अमित शाह संभालेंगे मोर्चा, बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में फोकस

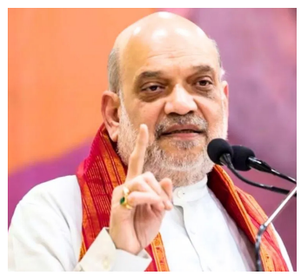

(जीएनएस)। साल 2026 भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनावी साल होने वाला है। इस साल पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी रणनीति पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मोर्चे की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है और इस महीने के अंत से वे पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इसके बाद जनवरी से हर महीने अमित शाह दो-दो दिन के लिए चुनावी राज्यों बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे।

बीजेपी का स्पष्ट उद्देश्य इन राज्यों में संगठन को मजबूत करना, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना और सहयोगी दलों के साथ तालमेल बैठाना है। अमित शाह अपने दौरे में जन-जागरूकता बैठकों, संगठनात्मक बैठकें और रैलियों के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाएंगे। वहीं, राज्यों में आचार संहिता लगने तक ये दौरे जारी रहेंगे ताकि पार्टी के रणनीतिक प्रयास लगातार प्रभावी बने रहें।

पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP ने संगठन स्तर पर व्यापक तैयारी की है। पार्टी ने भूपेंद्र यादव को बंगाल का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि विप्लव देव सह प्रभारी हैं। छह राज्यों के संगठन मंत्रियों को बंगाल के पांच बड़े चुनावी क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इसके अलावा छह वरिष्ठ नेताओं को भी जोड़ा गया है, जो आने वाले पांच महीनों तक बंगाल में सक्रिय रहेंगे।

बंगाल में केराढ़बंग क्षेत्र की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साईं के पास है। उनके साथ उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत भी हैं, ताकि पुरुलिया और वर्धमान जैसे क्षेत्रों में संगठन की जमीन मजबूत हो सके। हावड़ा, हुगली और मेदिनीपुर क्षेत्र में दिल्ली के संगठन मंत्री पवन राणा को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हावड़ा-हुगली में हरियाणा के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया और मेदिनीपुर संभाग में यूपी सरकार के मंत्री जेपी एसराठौर भी सक्रिय रहेंगे।

तमिलनाडु चुनाव की जिम्मेदारी इस बार विजयक जय पांडा को सौंपी गई है। उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि मुरलीधर मोहोल सह प्रभारी होंगे। पार्टी का उद्देश्य तमिलनाडु में संगठन को मज़बूत करना, स्थानीय मुद्दों और विकास एजेंडा के माध्यम से समर्थन जुटाना और सहयोगी दलों के साथ तालमेल को और प्रभावी बनाना है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस तरह की सक्रियता का उद्देश्य पार्टी के चुनावी राज्यों में सभी स्तरों पर संगठनात्मक मजबूती लाना है। उनका मानना है कि बूथ स्तर से लेकर राज्य नेतृत्व तक पार्टी की पूरी मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त करना ही सफलता की कुंजी है।

छिंदवाड़ा कफ सिरप कांडः 46% घातक रसायन के कारण बच्चों की मौत, केंद्रीय जांच में खुलासे

(जीएनएस)। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के अनुसार, जिन बच्चों ने कथित तौर पर कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' का सेवन किया, उनमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की खतरनाक मात्रा 46.28% पाई गई, जो किसी भी दवा में घातक और पूरी तरह प्रतिबंधित है।

सरकार ने बताया कि इस त्रासदी के बाद तत्काल केंद्रीय टीम का गठन किया गया, जिसमें महामारी विज्ञानी, सूक्ष्म जीव विज्ञानी, कीट विज्ञानी, एनसीडीसी और एनआईवी के विशेषज्ञ शामिल थे। इस टीम ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और नागपुर में जाकर विस्तृत जांच की और बच्चों द्वारा सेवन की गई कुल 19 दवाओं के नमूने निजी चिकित्सकों और स्थानीय खुदरा स्टोर्स से एकत्र किए। रासायनिक परीक्षण में 15 नमूने मानक गुणवत्ता के पाए गए, जबकि चार नमूनों में गंभीर गुणवत्ता उल्लंघन पाया गया।

विशेष रूप से तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ सिरप में 46.28% DEG की मात्रा मिली। निरीक्षण में निर्माता के भंडारण और विनिर्माण प्रक्रियाओं में कई गंभीर GMP (गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस) उल्लंघन सामने आए। इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु राज्य ने कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया और केंद्रीय औषधि नियामक ने आपराधिक कार्रवाई शुरू की।

मृत बच्चों को आपूर्ति की गई यह सिरप मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पुडुचेरी में उपलब्ध थी। संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने तुरंत इसे प्रतिबंधित कर वापस मंगाने का आदेश दिया। इसके साथ ही केंद्रीय औषधि नियंत्रक ने सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिया कि बाल चिकित्सा सिरप का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित किया जाए और नकली या घटिया दवाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा अब तक 700 से अधिक कफ सिरप निर्माताओं का गहन ऑडिट किया गया है। बाजार में उपलब्ध सिरप के नमूने बढ़ाए गए हैं और विनिर्माण प्रक्रियाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया कि सभी परीक्षण और गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके।

इस कांड ने बच्चों की सुरक्षा और दवा नियमन में गंभीर खामियों को उजागर किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले से सबक लेकर बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रमाणिक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कड़े मानक लागू किए जाएंगे।

देशभर के लोको पायलट दो दिन का उपवास बिना खाना खाए ट्रेन चलाकर जताएंगे विरोध

(जीएनएस)। देहरादून। देशभर के लोको पायलट मंगलवार से दो दिन के उपवास पर हैं। इसमें देहरादून के करीब 70 लोको पायलट भी शामिल हैं। इस दौरान वे अगले 48 घंटे तक बिना खाना खाए ट्रेन चलाएंगे। हालांकि रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस उपवास से ट्रेन संचालन प्रभावित नहीं होगा। ट्रेनें समय पर चलती रहेंगी, यात्रियों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उपवास के दौरान रनिंग रूम में खाना नहीं पकाया जाएगा, लेकिन ड्यूटी पर लगे लोको पायलट सभी नियमों का पालन करते हुए ट्रेन संचालन सुनिश्चित करेंगे।

यह विरोध कार्यक्रम देशभर के लोको पायलटों की लंबित मांगों को लेकर किया जा रहा है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA) के शाखाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि लोको पायलट लंबे समय से कई अहम मांगें उठा रहे हैं, जिन पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इन मांगों में मुख्य रूप से किलोमीटर भत्ते में संशोधन, नियमित भर्ती कर स्टाफ की कमी को दूर करना और लोकोमोटिव में शौचालय की व्यवस्था करना शामिल है। विनोद कुमार ने बताया कि स्टाफ की कमी लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण लोको पायलटों को लगातार लंबी ड्यूटी करनी पड़ रही है और उन्हें पूरा रेस्ट नहीं मिल पा रहा। इससे न केवल कर्मचारियों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ रहा है, बल्कि ट्रेन सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अब रनिंग स्टाफ में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लोकोमोटिव में शौचालय न होने के कारण उन्हें विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

लोको पायलटों ने कई बार ज्ञापन देने और विभागीय अधिकारियों से बैठकें करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने पर यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि उपवास के बावजूद वे अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। इस तरह उनका यह सामूहिक उपवास विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, जो कर्मचारियों की समस्याओं और रेलवे में सुधार की मांग को उजागर करता है।

रेलवे प्रशासन ने भी यात्रियों को भरोसा दिलाया है कि उपवास के बावजूद ट्रेन संचालन पूरी तरह सामान्य रहेगा। उपवास के दौरान लोको पायलटों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाएगा, और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस विरोध कार्यक्रम से देशभर में लोको पायलटों की मांगों पर केंद्र और रेलवे अधिकारियों का ध्यान जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

ग्वालियर में 31 दिन से लापता मासूम की गुमशुदगी पर 'मजिस्ट्रेट महादेव' की अदालत में फैसला, परिजन ने खाई कसम

(जीएनएस)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1 नवंबर से लापता 4 वर्षीय मासूम रितेश की गुमशुदगी अब स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। मोहनपुर गांव में अपने नाना के घर से अचानक गायब हुए रितेश को खोजने के लिए पुलिस ने 31 दिन तक लगातार खोजबीन और तकनीकी जांच की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। मासूम की मां सपना पाल, जो छह माह से पारिवारिक विवादों के कारण मायके में रह रही हैं, और पिता दलबीर सिंह सहित परिजन लगातार पुलिस से मदद मांगते रहे। पुलिस ने मां, पिता और रिश्तेदारों से पूछताछ की, जंगलों और आसपास के क्षेत्रों में खोज अभियान चलाया, लेकिन रितेश का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों की न्याय की अंतिम उम्मीद अब गिरगांव स्थित 'मजिस्ट्रेट महादेव' की अदालत में टिकी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि महादेव की अदालत में न्याय पाने वाले के लिए न्याय सुनिश्चित होता है और दोषियों को सजा मिलती है। इस विश्वास के तहत आज (मंगलवार) मंदिर परिसर में बघेल समाज की महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें मासूम के माता-पिता और सात से आठ रिश्तेदारों ने भाग लिया।

महापंचायत में एक पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें सभी परिजनों और रिश्तेदारों ने महादेव के समक्ष कसम खाई कि यदि किसी भी पक्ष का इस गुमशुदगी में हाथ है, तो वे अपने जान-माल का नुकसान भुगतने के लिए तैयार हैं। पंचों ने सर्वसम्मति से यह निर्देश दिया कि महादेव अगले पांच दिनों में दोषी पक्ष को दंडित करें। यदि इस अवधि में किसी को कोई नुकसान होता है या बच्चा बरामद नहीं होता, तो दोषी पक्ष पर हत्या या अपहरण का मामला दर्ज किया जाएगा। यदि इस अवधि में कोई नुकसान नहीं होता, तो माना जाएगा कि तीसरे पक्ष ने बच्चे का अपहरण किया है। महापंचायत में मासूम की मां सपना ने अपने दोनों भाइयों की जान की कसम खाई, जबकि पिता दलबीर ने विश्वास जताया कि भगवान न्याय करेंगे। रिश्तेदार टेकन सिंह ने स्वयं पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया और महादेव के समक्ष निष्पक्ष न्याय की उम्मीद जताई।

जालसाजी की नई मिसाल: राजस्थान के गांवों में फर्जी दिव्यांग पेंशन का खुलासा, लाखों रुपए सरकारी खजाने से निकले

(जीएनएस)। राजस्थान के झालावाड़ जिले में दिव्यांग पेंशन योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसने जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों को हैरान कर दिया है। जांच में पता चला कि कई गांवों में कागजों में ही लोगों को दिव्यांग दर्ज किया गया है और वे पेंशन के लाभ उठा रहे हैं, जबकि वास्तविक प्रमाण पत्र केवल कुछ ही लोगों को मिले हैं।

जिला प्रशासन के अनुसार, झालावाड़ की दो ग्राम पंचायतों में ही 1228 लोग फर्जी दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं। इससे हर महीने करीब 15 लाख रुपए सरकारी धन का भुगतान किया जा रहा है। मनोहरथाना पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 13,694 लोगों को दिव्यांग पेंशन दी जा रही है, जो इस क्षेत्र में इस योजना की बड़ी संख्या को दर्शाता है और सवाल खड़ा करता है कि इतने लोग वास्तविक रूप से दिव्यांग कैसे हो सकते हैं।

खाताखेड़ी ग्राम पंचायत की स्थिति सबसे चौंकाने वाली है। लगभग 5500 की आबादी वाले इस क्षेत्र में 982 लोग पेंशन ले रहे हैं, जबकि मेडिकल बोर्ड से केवल 70 प्रमाण पत्र ही जारी हुए हैं। यानी, पंचायत की कुल आबादी का 18 प्रतिशत हिस्सा केवल कागजों में दिव्यांग है। मदनपुरा गांव की स्थिति इससे भी गंभीर है। महज 800 की आबादी वाले इस गांव में 247 लोग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो कुल आबादी का 31 प्रतिशत बनता है।

आंवलहेड़ा ग्राम पंचायत की स्थिति भी अलग नहीं है। यहां केवल 59 लोग वास्तविक दिव्यांग हैं, लेकिन 375 लोग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से 316 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि ई-मित्र केंद्रों और बिचौलियों के माध्यम से बिना मेडिकल जांच, बिना अस्पताल गए और बिना प्रक्रिया का पालन किए फर्जी दस्तावेज बनाकर लाभ उठाया जा रहा है।

इस मामले के सामने आने के बाद झालावाड़ कलेक्टर अजय सिंह राठौर के निर्देश पर जांच को और तेज कर दिया गया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि ऑपरेशन 'शटर डाउन' के दौरान भी ऐसे मामले सामने आए थे। जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि यह मामला केवल कुछ ग्राम पंचायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जिले में ऐसे फर्जीवाड़े की जांच आवश्यक है। फर्जी दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित इस खुलासे ने सरकारी योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता की अहमियत को फिर एक बार सामने रखा है। स्थानीय प्रशासन अब सुनिश्चित कर रहा है कि आने वाले समय में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और वास्तविक जरूरतमंदों को ही योजना का लाभ मिले।

बिहार विधानसभा के 18वें स्पीकर के रूप में डॉ. प्रेम कुमार निर्विरोध चुने जाएंगे

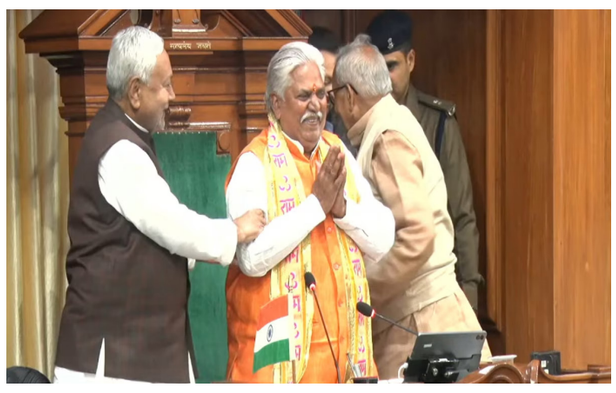

(जीएनएस)। पटना। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन डॉ. प्रेम कुमार का निर्विरोध चुनाव 18वें स्पीकर के रूप में होने जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गया से नौ बार विधायक रहे डॉ. कुमार अकेले उम्मीदवार होने के कारण उनका निर्वाचित होना लगभग तय माना जा रहा है। यह चुनाव विधानसभा की नई कार्यावधि में पहली महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जा रही है और इसके साथ ही सदन के संचालन और कार्य संस्कृति के लिए नए अध्याय की शुरुआत होगी।

डॉ. प्रेम कुमार पहली बार 1990 में विधायक बने थे और तब से लगातार जीतते हुए बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। उनके राजनीतिक करियर में 2015 से 2017 तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करना और विभिन्न मंत्रित्वकालों में महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार संभालना शामिल है। उनका अनुभव और राजनीतिक समझ सदन में नेतृत्व क्षमता को मजबूती प्रदान करेगी और विधानमंडल के सुचारू संचालन में सहायक सिद्ध होगी।

इस शीतकालीन सत्र में कुल पाँच बैठकें आयोजित की जाएंगी और यह 18वीं विधानसभा की पहली बैठक होगी। विधानसभा चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीतियों के साथ सदन में उतरेंगे। डॉ. प्रेम कुमार भाजपा कोटे से विजय कुमार सिन्हा और नंदकिशोर यादव के बाद तीसरे स्पीकर होंगे। उन्होंने सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के साथ संतुलित नेतृत्व प्रदान करने का अनुभव पहले भी साबित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेता के रूप में डॉ. कुमार की सादगी, पारदर्शिता और राजनीतिक पकड़ सदन में विभिन्न दलों के बीच संवाद और सहमति को बढ़ावा देगी। उनके नेतृत्व में विधानसभा में विधायी प्रक्रिया, बहस और कानून निर्माण की गति और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, डॉ. कुमार के स्पीकर बनने से बिहार विधानसभा की कार्यशैली में संतुलन और अनुशासन की नई दिशा देखने को मिलेगी। उनके अनुभव और निष्पक्ष दृष्टिकोण के कारण यह संभावना जताई जा रही है कि आगामी सत्रों में सदन में सक्रिय और परिणामकारी बहस होगी। इस निर्विरोध चुनाव के बाद विधानसभा में डॉ. प्रेम कुमार का नेतृत्व सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।

सौराष्ट्र में प्रेम कहानी बनी खौफनाक हकीकतः गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाला बॉयफ्रेंड हिरासत में ही हुआ मृत

(जीएनएस)। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में एक प्रेम कहानी ने खौफनाक मोड़ ले लिया, जब लिव-इन पार्टनर की हत्या के आरोप में पकड़ा गया युवक हिरासत में ही मृत हो गया। घटना ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी चौंका दिया है। मृतक युवक नरेंद्र सिंह ध्रुवेल, मूलतः मध्य प्रदेश का रहने वाला था, जबकि मृतक महिला पुष्पा देवी मरावी अनूपपुर, मध्य प्रदेश की निवासी थी। पुलिस के अनुसार, दोनों नरेंद्र और पुष्पा तीन महीने से सौराष्ट्र के एक सिरेमिक फैक्ट्री के वर्कर्स हॉस्टल में रह रहे थे और साथ काम कर रहे थे। शुक्रवार रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जो खौफनाक हिंसा में बदल गया। गुस्से में नरेंद्र ने पुष्पा को लकड़ी और बेल्ट से मारना शुरू किया। महिला की शारीरिक हालत गंभीर हो गई और उसने मदद की भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र ने रुकने का नाम नहीं लिया। इसी बीच उसने पुष्पा के चेहरे पर काटने तक की वार किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुष्पा का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि महिला की मौत गंभीर चोटों और शारीरिक अत्याचार के कारण हुई। घटना के बाद नरेंद्र ने अपना जुर्म कबूल किया और आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। हालांकि, रविवार सुबह करीब 4 बजे हिरासत में लिए गए नरेंद्र को सीने में तेज दर्द होने लगा। पुलिस ने तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नरेंद्र के परिवार को इस बारे में सूचित किया। अब यह मामला दोनों परिवारों और स्थानीय समाज में चर्चा का केंद्र बन गया है।

पुलिस ने बताया कि 25 वर्षीय नरेंद्र सिंह ध्रुवेल डिंडौरी, मध्य प्रदेश का रहने वाला था और मोरबी में लेक्सस सिरेमिक में मजदूरी करता था। वहीं 20 वर्षीय पुष्पा देवी अनूपपुर की रहने वाली थी। दोनों का प्रेम संबंध कुछ महीनों पहले शुरू हुआ था और इसके बाद वे सौराष्ट्र आकर साथ रहने लगे। वहीं, कुछ दिनों से उनके बीच झगड़े और विवाद शुरू हो गए थे।

फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के परिवारों से संपर्क साधा है और पूरे मामले की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना की पूरी स्थिति और हिरासत में युवक की अचानक मौत के कारणों की छानबीन की जा रही है। इस खौफनाक घटना ने स्थानीय समुदाय को स्तब्ध कर दिया है और प्रेम-हिंसा के इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।